



Neutral Citation No. - 2026:AHC:12712

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 16410 वर्ष 2025

अब्दुल कादिर उर्फ लालू

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक के अधिवक्ता:

आशुतोष तिवारी, यद्वेश यादव

विपक्षी के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता, ओम प्रकाश शर्मा, रवि प्रकाश

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. सूची को संशोधित किया गया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री आशुतोष तिवारी, मुखबिर के विद्वान अधिवक्ता श्री रवि प्रकाश एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अभिषेक मिश्रा को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।
3. आवेदक विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना- लोहता, जिला- वाराणसी में **मुकदमा अपराध संख्या 35 वर्ष 2025**, अंतर्गत धारा 3(5), 103(1), 238, 118(2) बी.एन.एस. (BNS) के तहत जमानत की मांग कर रहा है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त, **सुल्तान उर्फ टीपू** को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 35885 वर्ष 2025 में पारित आदेश दिनांक 29.10.2025 के माध्यम से पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। यह भी तर्क दिया गया कि चूंकि आवेदक का मामला उक्त सह-अभियुक्त के समान है जिसे पहले ही जमानत मिल चुकी है, इसलिए वह भी समानता (parity) के आधार पर जमानत पर रिहा होने का हकदार है।
5. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बताया कि आवेदक के नाम निर्दिष्ट आपराधिक इतिहास को शपथ-पत्र में स्पष्ट कर दिया गया है। आवेदक दिनांक 15.02.2025 से जेल में निरुद्ध है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता एवं मुखबिर के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है। हालांकि, उनके द्वारा सह-अभियुक्त के साथ समानता (parity) के उक्त तथ्यात्मक पहलू का खंडन नहीं किया गया है।
7. **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2020) 11 SCC 648** के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध कई आपराधिक मामलों का लंबित होना अपने आप में जमानत देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता।
8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों, लंबित विचारण और इस न्यायालय द्वारा **नन्हा पुत्र नभन खाँ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 Cri.L.J. 938** में पारित निर्णय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा **पारस राम विशनोई बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो, MANU/SCOR/22410/2021** एवं **सर्तेन्द्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, (2022) 10 SCC 51** में पारित निर्णयों के आलोक में, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का यह मत है कि आवेदक इस मामले में जमानत पर रिहा होने का हकदार है। समानता के आधार पर जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
9. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक- **अब्दुल कादिर उर्फ लालू** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व प्रतिभूओं का सत्यापन किया जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा।
- (iii) आवेदक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन के मामले में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(कृष्ण पहल, न्यायमूर्ति)

जनवरी 19, 2026

सिद्धांत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।